

राज्यपाल ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना' हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा

गत दिनों दिल्ली प्रवास पर केन्द्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से हुई थी चर्चा

लखनऊ: 02 सितम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के शहरी गरीब लोगों को सस्ती दरों पर आवास उपलब्ध कराने हेतु एक समेकित प्रस्ताव राज्य सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को जल्द भेजने को कहा है। पत्र में राज्यपाल ने कहा है कि "राज्यपाल होने के नाते मैं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य सेतु की भूमिका का निर्वहन करता हूँ।"

जातव्य है कि 30 अगस्त, 2016 को दिल्ली प्रवास के दौरान राज्यपाल की केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू से प्रदेश के विकास के संबंध में चर्चा हुई थी। श्री नायडू ने राज्यपाल राम नाईक को बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा शहरी गरीबों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराने हेतु 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का शुभारम्भ 25 जून, 2015 को हुआ था और इस योजना के अन्तर्गत 7 वर्षों में अर्थात् वर्ष 2022 तक दो करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के संबंध में श्री वेंकैया नायडू ने राज्यपाल को अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक इस योजना के अन्तर्गत कोई प्रस्ताव केन्द्र को नहीं भेजा गया है जबकि उनके द्वारा एवं मंत्रालय के सचिव द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार से पत्र व्यवहार किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि 'प्रधानमंत्री आवास योजना' हेतु 21 राज्यों ने केन्द्र सरकार को अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं।

पत्र में राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश के विकास के दृष्टिगत मुख्यमंत्री प्राथमिकता के आधार पर 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने पर शीघ्र निर्णय लेंगे।
